

अतः पत्रपत्रो द्वारा नुसार दिनांक 5-7-2021 को पेश हो।
रीज

17-7-2021 वकील द्वारा कन्डोलेंस | वास्ते जबाब न. 1. प्रा०पत्र पत्रावली दि० 12-7-2021 को पेश हो। न. 1. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०भा०)

12-7-2021 वकील उमयपक्ष उप० | वास्ते जबाब न. 1. प्रा०पत्र पत्रावली दिनांक 19-7-2021 को पेश हो। न. 1. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।

19-7-2021 वकील उमयपक्ष उप० | वकील अप्रार्थी जबाब प्रस्तुत करने को समय चाहते हैं। अतः वास्ते जबाब पत्रावली दि० 20-7-2021 को पेश हो।

20-7-2021 वकील उमयपक्ष उप० | वकील अप्रार्थी ने जबाब न. 1. प्रा०पत्र एवं फर्द के साथ 15 दस्तावेज प्रस्तुत किए। बहस हेतु समय चाहते हैं। अतः वास्ते बहस पत्रावली दि० 23-7-2021 को पेश हो। न. 1. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।

23-7-2021 वकील उमयपक्ष उप० | वास्ते बहस पत्रावली दि० 26-7-2021 को पेश हो। न. 1. आदेश आगामी पेशी तक बढ़ाया जाता है।

26-7-2021 वकील उमयपक्ष उप० | न. 1. प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। न. 1. प्रा०पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा दि० 26-5-2021 को जारी अन्तरिम अस्थायी विधेयाज्ञा आदेश लागू किया जाता है। पत्रा० पेशी होकर नम्बर से काम हो एवं बाद तक मूल वाद के साथ संबन्ध रहे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०भा०)

उप
गंग

6/22

1. राधादेवी पत्नी स्व० जुगनू

2. आकारा पुत्र जुगनू

3. कपिल पुत्र जुगनू

4. दानप्रकाश पुत्र किशनलाल

5. नेहा पुत्री जुगनू

6. पूजा पुत्री जुगनू

7. हरप्यारी पत्नी किशनलाल

समस्त जाति रैगर (जाटव) निवासी मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी जिला
सवाई माधोपुर

नाबालिक द्वारा प्राकृतिक संरक्षिका
माता राधादेवी पत्नी स्व. जुगनू

बनाम

1. राजूलाल पुत्र मीठालाल मीना निवासी ग्राम टुंडीला तहसील बामनवास

2. शिवकुमार पुत्र रामस्वरूप, महाजन निवासी लाटा हाउस के पास, उदेई
मोड, गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

3 तहसीलदार गंगापुर सिटी

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी न० 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है जिनकी तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि आराजी ख० नं० 170 रकबा 0.55 है० वाके ग्राम हिगोटिया तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नहीं है, न ही कभी रहा है। न ही कभी हो सकता है। विवादित आराजी भूमि पर प्रार्थीगण प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही साल दर साल काशत करते हुए लाभान्वित होते आ रहे हैं व वर्तमान में भी अपनी तन्हा खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि का उपयोग व उपभोग कर लाभान्वित होते आ रहे हैं। विवादित आराजी भूमि से अप्रार्थी सं० 1 व 2 का किसी भी प्रकार का कोई संबंध सरोकार हक हिस्सा अधिकार नहीं रहा है न ही वर्तमान में है। फिर भी अप्रार्थी सं० 1 व 2 अपने राजनैतिक प्रभाव व लाठी के जोर पर विवादित आराजी भूमि में जबरन प्रार्थीगण के कब्जे काशत में व प्रार्थीगण के उपयोग व उपभोग में अनुचित

EX

गंगापुर सिटी (स०मा०)



नी प्रकार का कोई लिखित नहीं है। प्रमाण गरीब लड़के का कर्तव्य
 व्यक्ति हैं जो अपनी बरजी भूमि पर कास्त आदि कार्य करके अपना एवं
 अपने परिवार का गुजर बसर करते चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में प्रार्थीगण
 अपनी तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की विवादित भूमि पर अपनी भूमि की
 सुरक्षार्थ उक्त भूमि के चारों तरफ बाउण्ड्री बाल का निर्माण किया जा रहा है।
 इसमें भी अप्रार्थी सं० 1 व 2 अनुचित रूप से व्यवधान उत्पन्न करते हुए
 विवाद उत्पन्न कर रहे हैं तथा दिनांक 12.05.2021 को जब प्रार्थीगण द्वारा
 अपनी आराजी भूमि पर बाउण्ड्री का निर्माण किया जा रहा था तब अप्रार्थी सं०
 1 व 2 अपने सहयोगियों एवं दीगर व्यक्तियों को साथ लेकर आ गया एवं
 विवादित भूमि में जबरन प्रवेश करने का असफल प्रयास करते हुए प्रार्थीगण
 को बाउण्ड्री बाल का निर्माण करने से रोकने लग गये एवं लडाईं झगडा करने
 पर उतारू हो गये तब पुलिस प्रशासन ने सूचना पर आकर अप्रार्थी सं० 1 व
 2 को समझाया तथा अप्रार्थी सं० 1 व 2 अपने सहयोगियों व दीगर व्यक्ति के
 साथ वहां से चले गये परन्तु इसके उपरान्त अप्रार्थी सं० 1 व 2 बारम्बार
 प्रार्थीगण को विवादित भूमि बांवात् धमकी देते रहे तथा दिनांक 21.05.2021 को
 अप्रार्थी सं० 1 व 2 तथा उनके परिजन एकराय होकर विवादित भूमि पर
 आकर प्रार्थीगण को जान से मारने की धमकी देते हुए चेतावनी देने लगे कि
 इस भूमि पर तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे एवं इस भूमि पर कब्जा काश्त करके
 रहेंगे और तुम्हे सुरक्षा दीवार नहीं बनाने देंगे। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई
 निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिए
 अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण की
 तन्हा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि आराजी ख० न० 170 रकबा 0.55 है० ग्राम
 हिगोटिया तह० गंगपुर सिटी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, बुबाई जुताई, कृषि
 कार्य, विकास कार्य तथा किसी भी प्रकार का सुधार कार्य करने कराने में
 विवाद या दखलअंदाजी नहीं करे और ना ही किसी अन्य से करावे। उक्त
 भूमि में स्थित पेड पौधो, कृषि संसाधनों, बाउण्ड्री, तारबंदी आदि को किसी
 प्रकार की क्षति नहीं पहुचावे, भूमि में जबरन प्रवेश कर भूमि पर कब्जा करने
 का प्रयास नहीं करे, न करावे, भूमि से जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का
 प्रयास न करे, ना करावे। प्रार्थीगण को उक्त भूमि में सुरक्षा दीवार,
 बाउण्ड्रीवाल करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, ना करावे।
 स्वयं अपने सेवको, साथियो, परिवारजनों, रिश्तेदारो, वारिसानों व सहयोगियो
 सहित ता फैसला वाद प्रतिबंधित रहे।

ता कलेक्टर
 तह (स० गा०)



प्रार्थना पत्र दर्ज करके दिया जाकर अप्रार्थीगण को बलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बड़जुड़ उपस्थित नहीं हुआ।

अप्रार्थी सं० 1, 2 की ओर से जबाब इस आशय का पेश किया गया कि विवादित भूमि को पूर्व में ही खातेदार द्वारा आवासीय प्रयोजन के लिये विक्रय किया जा चुका है समस्त भूमि में आवासीय मकान काफी लम्बे समय के बने हुये हैं तथा राज्य सरकार द्वारा भी उक्त भूमि में विकास के कार्य करवाये जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा रोड भी बनाई जा चुकी है विद्युत लाईन भी पूरी कॉलानी में लगी हुई है तथा पूरी कॉलोनी में सिवरेज लाइन भी डल चुकी है। उक्त भूमि 30 साल से भी लम्बे समय से काबिल काश्त नहीं रही है। आवासीय प्रयोजन के रूप में काम में ली जा रही है। प्रार्थीगण द्वारा गलत रूप से उक्त भूमि अपनी खातेदारी में होना बताकर, काबिल काश्त होना बताकर उक्त दावा गलत रूप से पेश किया है जबकि भूमि पर अरसा करीब 30 साल से उनका कोई कब्जा नहीं है। बिना कब्जे के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है। इस भूमि में कॉलोनी अग्रवाल फार्म के नाम से बनी हुयी है। मामले मे अदालत हाजा के आदेश से तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार की गयी है जिसमें भी उक्त भूमि में आवासीय मकान बने होना, विद्युत पोल लगे होना, सीवरेज लाईन डलना तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोटिया का मुख्य रास्ता भी इसी भूमि में होकर जाना बताया है। कॉलोनी मे करीब 100 से अधिक मकानात बने हुये हैं। दि० 12-05-21 को एवं 21-05-21 को किसी प्रकार की कोई घटना ही घटित नहीं हुयी, प्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छुपाते हुये यह गलत दावा पेश किया है। प्रार्थीगण क्लीन हेण्ड से अदालत के समक्ष नहीं आये है। इसलिए उन्हें अस्थायी निषेधाज्ञा जैसी रेमेडी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। बिना कब्जे के प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी भी नहीं है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन ने प्रार्थीगण ने छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत 2071-2074 ग्राम हिंगोटिया खाता संख्या 33, छायाप्रति नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के जबाब के समर्थन ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से स्टाम्प पर लिखे गये विक्रय पत्रो (1 लगायत 15) की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की है।

दावे मे प्रतिवादीगण की ओर से मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा दावे मे वादग्रस्त भूमि ख०न० 170

जला कलेक्टर
सिटी (स०मा०)



ग्राम हिगोटिया की नई की स्थिति की स्ट्रीट बनाई गई। जो मूल वाद में दर्ज है।

बहस विद्वान वकील समयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जो उनके द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति नकल जमाबंदी संवत् 2071-74 ग्राम हिगोटिया खाता संख्या 33 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को भूमि का कोई बेचान नहीं किया है। यदि बेचान किया होता तो जमाबंदी में इसका अंकन होता। जो दस्तावेज अप्रार्थीगण ने अपने जबाब के साथ प्रस्तुत किये हैं उनसे भी यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कभी कोई नूनि का बेचान नहीं किया। वादग्रस्त भूमि आज भी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण को भूमि के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भूमि पर कब्जे का प्रश्न है तो खातेदार होने के नाते भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा माना जावेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना प्रथम दृष्टया साबित है। फलस्वरूप अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को बरसो पहले ही विक्रय कर चुके हैं जो अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्रों की छायाप्रतियों से प्रमाणित है एवं मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। यह बात तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में मकान बने हुए हैं, बाउन्ड्रीशुदा कई प्लॉट बने हुए हैं, आवागमन हेतु भूमि में रास्ता बना हुआ है, भूमि में सीवरेज लाईन डली हुई है तथा भूमि के आस पास आबादी बसी हुई है। भूमि पर कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा या स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर अपना कब्जा प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। अपने इस कथन के समर्थन में अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने न्याय दृष्टान्त 2021 (1) डी.एन.जे. (राजस्व) पेज 69 प्रस्तुत किया है। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तीन बिन्दुओं 1. प्रथम दृष्टया केस 2. सुविधा संतुलन 3. अपूरणीय क्षति पर विचार किया जाना आवश्यक है।

कलेक्टर



इसके साथ ही कब्जे का बिन्दू भी इन्हें नहत्वपूर्ण होता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों में नकल खंडों संवत् 2071-74 के अनुसार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से जबाब के साथ प्रस्तुत 15 किता छायाप्रति विक्रय पत्रों के अनुसार इस भूमि का भूखण्डों के रूप में बेचान हो चुका है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इन दस्तावेजों के खंडन में प्रार्थीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर भूखण्डों के रूप में बेचान हो चुका है एवं भूमि पर वर्तमान में काश्त नहीं होती है। इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय द्वारा मंगवाई गई मौका रिपोर्ट में भी तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अंकित किया है कि मौके पर उक्त खसरा नम्बर में छितराई हुई आकृति में पुष्पा मकान बने हुए है, बाउन्ड्रीशुदा कई प्लॉट बने हुए है, आवागमन हेतु उक्त खसरा नम्बर में एक रास्ता बना हुआ है एवं उक्त खसरा नम्बर के आस पास ही आबादी बसी हुई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर प्रार्थीगण कृषि पर कब्जे में नहीं है। चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में कब्जा नहत्वपूर्ण बिन्दू है एवं कब्जे के अभाव में प्रार्थीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होता है। इसी प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं जाते हैं। फलस्वरूप प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं इस न्यायालय द्वारा 26.5.2021 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश वापिस लिया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 26.7.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अनिल कुमार चौधरी)
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी (सं०मा०)